10 जनवरी, 2013

होर्मज जलडमरूमध्य को बंद करने की ईरान की धमकी

*डॉ. आसिफ शूजा **

28 दिसम्बर, 2012 को ईरान ने अपने युद्धक जहाजों, पनडुब्बियों और जेट लड़ाकु विमानों को शामिल करते हुए होर्मज जलडमरूमध्य में अपने छह दिवसीय वार गेम को शुरू किया जिसका कूट नाम 'वेलायत 91' था। इस सैन्य अभ्यास में होर्मज जलडमरूमध्य, ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर के उत्तरी भाग का लगभग एक मिलियन वर्ग किलोमीटर का हिस्सा शामिल है। यद्यपि ईरानी नौसेना कमांडर हबीबुल्लाह सय्यारी ने आश्वस्त किया कि इस सैन्य अभ्यास की प्रकृति अनिवार्य रूप से रक्षात्मक है , इसलिए इस घटनाक्रम को विश्व द्वारा ईरान और पश्चिमी ताकतों के बीच वर्तमान परमाणु गतिरोध के साथ संबद्धता के कारण उत्सुकता से देखा जा रहा है।

ईरान अपने तेल राजस्व को पश्चिमी देशों द्वारा निशाना बनाने को रोकने के लिए पिछले कुछ समय से होर्मज जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी देता रहा है। वास्तव में ईरान ने दिसम्बर , 2011 में इसी प्रकार का दस दिवसीय सैन्य अभ्यास किया था। अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए कई आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान की अपनी तेल -निर्यात क्षमता में अत्यधिक कटौती करना पड़ा जो कि उसकी अर्थव्यवस्था का जीवन -रक्त है। होर्मज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इस चोक प्वाइंट पर किसी प्रकार के बाधा से तेल बाजार पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाएगी।

इस धमकी की तीव्रता इस तथ्य से देखी जा सकती है कि होर्मज जलडमरूमध्य को बंद करने संबंधी विधेयक पर जुलाई, 2012 में ईरानी संसद सके आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन था। तथापि, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमैनी, जो देश के सशस्त्र बल का नेतृत्व करता है , इस मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए सर्वोच्च अधिकारी है। इस संबंध में उनके निर्णय में ऐसी कार्रवाई के रणनीतिक अनिवार्यता संबंधी उनकी संगणना शामिल होगी। कि होर्मज जलडमरूमध्य को बंद किए जाने का मुद्दा और ईरान पर पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंध उसके विवादित परमाणु कार्यक्रम से संबद्ध है और इस कार्यक्रम की समीक्षा से इस संगणना के हावी होने की संभावना है।

ईरान ने इस जलडमरूमध्य के निकट व्यापक सैन्य तैयारी की है जिसे वह अपनी द्रूत गति नौकाओं, मिसाइल युक्त जहाजोंऔर समुद्री माइन्सों की मदद से प्राप्त कर सकता है। तथापि, अमेरिका, जिसने यह घोषणा की है कि ऐसा कोई कार्य उसे स्वीकार्य नहीं होगा और उसने भी इस जलमरूमध्य को पुन: खोलने के लिए स्वयं की तैयारी कर ली है। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में अति उन्नत अमेरिकी सैन्य तैनाती के विरूद्ध ईरानी असममित संघर्ष की रणनीति के दीर्घकाल में सफल होने की संभावना बहुत कम है।

दूसरी ओर, इस जलडमरूमध्य के बंद होने से ईरान का अपने तेल को निर्यात करने और आवश्यक वस्तुओं के आयात का मार्ग भी अवरूद्ध हो जाएगा। ईरान के निर्यात राजस्व का तीन भाग तेल निर्यात से आता है और यह उसके कुल राजस्व के 60 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे परिदृश्य में यह तर्क दिया जा सकता है कि इस जलडमरूमध्य को बंद कर ईरान अपने ही हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए, यह संभव है कि ईरान विकट परिस्थिति में ही अपनी धमकी पर कार्य करे जब हर कोई उसके तेल को खरीदना बंद कर दे। वर्तमान में , इस परिदृश्य को आसानी से छोड़ा जा सकता है क्योंकि ईरान के बड़े तेल खरीददार यथा चीन और भारत ने ईरान के साथ अपने तेल व्यापार को बंद करने से मना कर दिया है। यह आंशिक रूप से ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से इन देशों को मिली छूट दर्शाता है।

इस व्याप्त तथ्य के विपरित ईरान द्वारा होर्मज जलडमरूमध्य को बंद किए जाने से वास्तव में अमेरिका को अपने

दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुविधा मिल सकती है। अब तक अमेरिका के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए एक पूर्ण अंतरराष्ट्रीय आम सहमति तैयार करना कठिन रहा है। ईरान के इस जलडमरूमध्य को बंद करने का प्रयास यथा स्थिति में परिवर्तन कर सकता है बशर्ते कि अमेरिका के पास इस कृत्य को सैन्य रूप से निपटाने में आवश्यक अंतरराष्ट्रीय वैधता जुटाने का आसान अवसर हो। तथापि , इस मामले में सैन्य कार्रवाई को केवल इस जलडमरूमध्य को खोले जाने तक सीमित नहीं रखा जा सकता है बल्कि इससे आगे जाकर ईरान की सैन्य और परमाणु अवसंरचना को ध्वस्त किया जा सकता है। परिणामस्वरूप होर्मज जलडमरूमध्य को वास्तविक रूप से बंद किए जाने से ईरान की अपनी रणनीतिक क्षमता को नुकसान हो सकता है।

इन परिस्थितियों में खमैनी के पास दो विकल्प हैं। प्रथम विकल्प है कि वे पश्चिमी प्रतिबंधों को चुपचाप सहन करे। हलांकि इसका अर्थ देश की आर्थिक स्थिति को और कमजोर करना होगा जो ईरान के खुले रूप में अस्वीकार किए जाने के बावजूद पहले से ही ध्वस्त है। मुख्य परमाणु समझौताकर्ता के रूप में सईद जलाली को अपने व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में मुख्य घोषित करने के हाल के परमाणु समझौते में खुमैनी का सीधा हस्तक्षेप देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंधों के प्रभाव के कारण वर्तमान परमाणु गतिरोध को समाप्त करने की उनकी इच्छा का संकेत है। लंबे समय तक प्रतिबंध लगे रहने से ईरान की स्थिति ईराक जैसी होने की संभावना है । उदाहरण के लिए , ईराक पर वर्षों तक कठोर प्रतिबंध लगे रहने से उसकी अर्थव्यवस्था इस बुरी तरह से ध्वस्त हो गयी कि बहुत अधिक प्रतिरोध के बिना ही अंतिम हमले में कमजोर सद्दाम के शासन को आसानी से समाप्त कर दिया गया।

खुमैनी के पास दूसरा विकल्पजो सुनने में कठिन लगता है किंतु इस पर विचार करना अतार्किक नहीं हो सकता है। इस विकल्प में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध शामिल हो सकता है - प्रतिबंधों में छूट के बदले कुछ समय के लिए प्रतिबंध। स्पष्ट रूप में खुमैनी वर्तमान में उसी स्थिति का सामना कर रहा है जिस स्थिति का सामना ईरान -इराक के बीच लगभग 8 वर्ष के युद्ध में 1998 में ईरान के प्रथम सर्वोच्च नेता और उसके पूर्ववर्ती अयातोल्लाह खुमैनी ने किया था। उस युद्ध ने ईरान को इतनी क्षति पहुंचाई कि बहुत आगे बढ़ने के बावजूद खुमैनी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा दिए गए युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा। खुमैनी के लिए इस युद्ध विराम से सहमत होना जहर पीने से भी अधिक बुरा था। अपने देश को इस बुरी हालत से बचाने के लिए खुमैनी इस्लामी गणतंत्र ईरान के इतिहास के इन पन्नों को दुबारा पलट सकता है।

*डॉ. आसिफ शूजा,भारतीय विश्व मामले परिषद, नई दिल्ली में अध्येता हैं

*

अस्वीकरण: व्यक्त मंतव्य लेखक के हैं और परिषद के मंतव्यों को परिलक्षित नहीं करते।